POSTAL REG. NO. JAIPURCITY/410/2015-17 (RNI. REG. NO. 39658/1983) # ग्रा.ग./2016/अंक 11

मासिक प्रेषण दि. 8 नवम्बर, सी.एस.ओ., आरएमएस गाँधी नगर, जयपुर-15

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

8 नवम्बर, 2016 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम! साथ ही 'ग्राम गदर' के सभी पाठकों को मेरी एवं 'कट्स' परिवार की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं! लक्ष्मी के आगमन की प्रतिक्षा में हर साल की तरह इस बार भी आप सभी ने साफ-सफाई कर अपने घर को स्वच्छ बनाया होगा। साथ कूड़ा कचरा एकत्रित कर गांव से दूर एक निश्चित स्थान पर डाला होगा।

संभवतः आपने अपने घर में शौचालय भी बनवा रखा होगा। यदि हां, तो आप हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के अनुसार सच्चे 'स्वच्छाग्रही' हैं। आपको अब गांव के सभी ग्रामीण भाई-बहिनों को जागरूक कर गदंगी के प्रति नफरत का माहौल तैयार करना होगा। जिससे पूरा गांव हमेशा स्वच्छ और निर्मल बन सके। सभी ग्रामवासी मन में ठान लें, तो यह काम मुश्किल नहीं होगा। क्योंकि, गदंगी किसी को भी पसंद नहीं होती।

मोदी के 'स्वच्छ भारत मिशन' ने दो अक्टूबर को दो साल पूरे कर लिए हैं और दो अक्टूबर 2019 तक सम्पूर्ण भारत को स्वच्छ एवं खुले में शौच से मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। अगले तीन सालों में इस काम को मंजिल तक पहुंचाने के लिए सभी को सहभागी बनकर अभियान से जुड़ना होगा। हर व्यक्ति को 'स्वच्छाग्रही' बनना होगा। हर चुनौती का सामना करते हुए इस काम को पूरा करने का बीड़ा उठाना होगा।

देश की आजादी के लिए गांधीजी के सत्याग्रह में जिस तरह हर देशवासियों ने जुड़कर हिस्सा लिया था उसी तरह स्वच्छाग्रह में सभी सहभागी बने तो यह सपना असंभव नहीं है। खासतौर से सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं के साथ इस काम को अंजाम देने के लिए देश की युवा शक्ति को आगे लाया जाए। देश के नागरिक होने के नाते हम संकल्प लें कि हम हमारे आस-पास गंदगी नहीं फैलाएंगे।

पत्नी मां-बाप के प्रति दायित्व नहीं निभाने देती तो हो सकता है तलाक

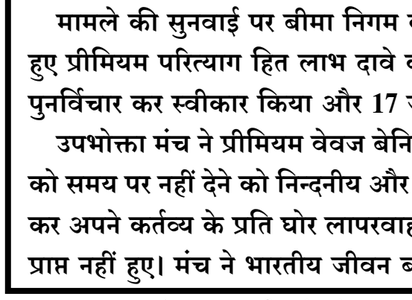

यह है मामला

मामले के अनुसार कर्नाटक की इस दम्पति की शादी के कुछ दिनों बाद से ही महिला अपने पति पर अकेले रहने का दबाव बना रही थी। उसकी क्रूर हरकतों की वजह से पति ने निचली अदालत में तलाक की अर्जी दी थी। अदालत ने इसे मंजूर कर लिया। बाद में हाईकोर्ट ने महिला का पक्ष लिया और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने तलाक को मंजूरी दे दी।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि यदि कोई महिला अपने पति को बूढे मां-बाप से अलग रहने को मजबूर करती है तो उसे पति तलाक दे सकता है। कोर्ट ने कहा है कि हिन्दू लॉ के मुताबिक कोई भी महिला किसी भी बेटे को उसके मां-बाप के प्रति दायित्वों के निर्वहन से मना नहीं कर सकती।

जस्टिस ए.आर.दवे और जस्टिस एल.एन राव की बैंच ने कहा कि एक महिला शादी के बाद पति के परिवार की सदस्य बन जाती है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि माता-पिता से अलग रहने की सोच हमारी सभ्यता और संस्कृति के खिलाफ है।

कोर्ट ने कर्नाटक के एक दम्पति के तलाक की अर्जी को मंजूरी देते हुए यह टिप्पणी की है। कोर्ट ने यह भी कहा कि पत्नी द्वारा बार-बार खुदकुशी की धमकी देना क्रूरता है। यह भी तलाक का आधार हो सकता है। ऐसे में कोई भी पति सकून से नहीं रह सकता।

भारतीय जीवन बीमा निगम पर 65 हजार रुपए का हर्जाना

जयपुर स्थित मानसरोवर निवासी इन्द्रा गर्ग ने अपने वकील यतीन्द्र प्रकाश शर्मा के माध्यम से 8 अप्रेल 2010 को उपभोक्ता मंच-तृतीय में भारतीय जीवन बीमा निगम के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया। परिवाद में बताया गया कि इन्द्रा गर्ग के पति अरविन्द कुमार ने नाबालिग पुत्री अनुश्री गर्ग के नाम से एक पॉलिसी प्राप्त की थी। 30 मार्च 2006 को अरविन्द कुमार की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने की सूरत में उक्त पॉलिसी के तहत आगे की प्रीमियम राशि की अदायगी का उत्तरदायित्व समाप्त हो जाता है। लेकिन बीमा कंपनी की ओर से बकाया बताकर उन्हें हैरान व परेशान किया गया है।

मामले की सुनवाई पर बीमा निगम की ओर से बताया गया कि भूलवश कालातीत मानते हुए प्रीमियम परित्याग हित लाभ दावे को 25 जुलाई 2006 को निरस्त कर दिया था। बाद में पुनर्विचार कर स्वीकार किया और 17 जून 2010 को पत्र द्वारा सूचित भी कर दिया गया था।

उपभोक्ता मंच ने प्रीमियम वेवज बेनिफिट (अग्रिम किश्तें माफ होना) का लाभ बीमाधारक को समय पर नहीं देने को निन्दनीय और खेदजनक माना और कहा कि बीमा कंपनी ने जानबूझ कर अपने कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही और उदासीनता बरती है, जिससे समय पर बेनिफिट प्राप्त नहीं हुए। मंच ने भारतीय जीवन बीमा निगम पर 65 हजार रुपए का हर्जाना लगाया है।

किसानों ने जाने जैविक खेती के फायदे

'कट्स' मानव विकास केन्द्र, चित्तौड़गढ़ की ओर से स्थानीय किसान भवन में जिला स्तरीय कृषक आमुखीकरण कार्यशाला रखी गई। केन्द्र समन्वयक गौहर महमूद ने जैविक खेती से किसानों को होने वाले लाभों से परिचित कराते हुए बताया कि 'कट्स' द्वारा जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए एसएसएनसी स्वीडन के सहयोग से प्रो-आर्गेनिक परियोजना चलाई जा रही है।

कार्यशाला में ग्राह्य अनुसंधान केन्द्र के कृषि अनुसंधान अधिकारी डॉ. ओ.पी. शर्मा ने जैव तकनीक के द्वारा कीट प्रबंधन के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि किसान फिर से जैविक खेती अपनाएं। राजस्थान स्टेट बीज निगम लि. के सयंत्र प्रबंधक डॉ. राजाराम सुखवाल ने जैविक प्रमाणीकरण और विपणन की विधियों की जानकारी दी। जयपुर स्थित कट्स-कार्ट के डिप्टी हेड दीपक सक्सेना ने कहा कि प्रदेश के छह जिलों में स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए पायलट परियोजना चल रही है।

परियोजना अधिकारी राजदीप पारीक ने किसानों को जैविक खाद और कीटनाशक तैयार करने की विधि बताकर किसानों को अपने घर में ही खाद व कीटनाशक तैयार करने को प्रेरित किया । किसानों को जयसिंहपुरा जैविक कृषि फार्म का शैक्षणिक भ्रमण भी कराया गया।

त्योहार पर लगा बिजली बिल का करंट

प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को छह साल में पांचवी बार महंगी बिजली का करंट झेलना पड़ रहा है। घरेलू बिजली में 35 पैसे से 75 पैसे, व्यावसायिक श्रेणी में 95 पैसे व औद्योगिक श्रेणी में 80 पैसे प्रति यूनिट तक की बढ़ोतरी की गई है। नई दरें एक सितम्बर से लागू की गई है।

इसके अलावा सभी श्रेणियों के स्थाई शुल्क में भी 20 से 30 रुपए प्रति माह बढ़ाए गए हैं। बीपीएल, कृषि व 50 यूनिट तक हर माह बिजली उपभोग करने वाले छोटे उपभोक्ता की जेब पर भी असर पड़ेगा। अब बीपीएल परिवारों को 25 पैसे, छोटे उपभोक्ताओं को 35 पैसे और किसानों को 25 से 35 पैसे प्रति यूनिट अतिरिक्त देने होंगे। ऊर्जा राज्यमंत्री पुष्पेन्द्र सिंह ने स्पष्ट किया है कि उक्त तीनों श्रेणियों में वर्तमान में दी जा रही सब्सिडी यथावत रहेगी।

चिकित्सक तो चाहते हैं गांवों में जाना

चिकित्सा विभाग हमेशा यह कहता रहा है कि डॉक्टर गांवों में जाना नहीं चाहते। जबकि स्थिति इससे बिल्कुल उलट है। डॉक्टर तो ग्रामीण क्षेत्रों में जाना चाहते हैं लेकिन विभाग खुद उन्हें नहीं भेज रहा है।

दरअसल, एमबीबीएस करने के बाद डॉक्टरों को गांवों में तीन साल की सेवा देने के बाद ही सीएस पीजी में प्रवेश मिल सकता है। लेकिन अब उनके सामने मुसीबत यह हो गई है कि विभाग ने उन्हें शहरों में ही लगा दिया है। ऐसे डॉक्टर जो आगे अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं वे अब गांव में लगाने के लिए विभाग के अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं।

सोलर पंप पर मिल सकेगी राहत

प्रदेश में किसानों को बिजली के बोझ से बचाने के लिए सरकार सोलर पंपों पर 85 फीसदी तक अनुदान देने की तैयारी कर रही है। फिलहाल इसका प्रस्ताव ऊर्जा विभाग तैयार कर रहा है। अभी सरकारी स्तर पर मंजूरी मिलने की प्रक्रिया बाकी है।

जानकारी के अनुसार प्रदेश में यह योजना लागू हुई तो पहले उन किसानों को फायदा दिया जाएगा, जिनके तीन व चार हॉर्सपावर के कनेक्शन लंबित पड़े हैं। योजना लागू होने पर किसान को सोलर पंप खरीदने पर केवल 15 फीसदी राशि ही चुकानी पड़ेगी। इससे किसान को बिजली बिल में काफी हद तक राहत मिलेगी।

नहीं बन पा रहे मृदा स्वास्थ्य कार्ड

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की महत्वाकांक्षी 'मृदा स्वास्थ्य कार्ड' योजना राज्य में दम तोड़ती नजर आ रही है। प्रदेश में 23.08 लाख मिट्टी के नमूने लेकर 70 लाख मृदा स्वास्थ कार्ड बनाकर किसानों को देने का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन अभी तक करीब 30 प्रतिशत से भी कम किसानों के ही मृदा स्वास्थ्य कार्ड बने हैं।

किसानों के खेत से लिए गए मिट्टी के नमूनों का परीक्षण प्रयोगशाला में होना था, लेकिन सरकारी स्तर पर बहुत कम प्रयोगशालाएं होने और पीपीपी मोड पर बनने वाली प्रयोग-शालाओं में भी देरी होने से किसानों तक मृदा स्वास्थ्य कार्ड नहीं पहुंच पा रहे हैं।

गांव के गरीबों के राशन पर डाका

उदयपुर के लक्ष्मणपुरा गांव में गरीबों के राशन का गेहूं, आटा मिल मालिक हड़प कर रहे हैं। पकड़े गए ट्रक में 302 कट्टे राशन के गेहूं के थे, जो गोगूंदा क्रय-विक्रय समिति को भेजे गए थे। यह गेहूं वहां नहीं पहुंचा। अन्य ट्रक में लदान कर डबोक के लक्ष्मणपुरा आटा मिल में पहुंचा दिए गए।

पिछले दिनों प्रतापगढ़ थाना क्षेत्र के मादड़ी इंडस्ट्रीयल एरिया में भी सगड़ा क्रय-विक्रय समिति में राशन के सामान में हेराफेरी का भांडा फूटने के बावजूद यह खेल थम नहीं रहा। आपसी मिलीभगत के चलते मुनाफे का यह खेल लम्बे समय से चल रहा है। इसकी जानकारी रसद विभाग को भी है। लेकिन विभाग के जिम्मेदार अफसर हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं।

गंदगी के प्रति हो नफरत का माहौल

गंदगी किसी को पसंद नहीं, लेकिन कोई इसे दूर करने की हिम्मत नहीं करता। गदंगी के प्रति नफरत का माहौल होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के आम लोगों को यह सन्देश देते हुए कहा कि शहर ही नहीं गांवों तक सफाई के प्रति जागरूकता बढ़े, यह जरूरी है।

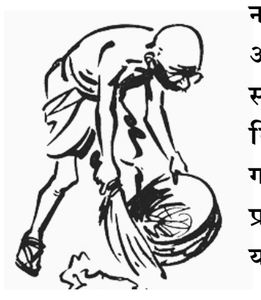

मोदी ने कहा कि स्वच्छता सिर्फ प्रधानमंत्री का मिशन नहीं है। स्वच्छता अभियान को लेकर सरकार के साथ-साथ राजनेता, जनप्रतिनिधियों और आम जन को आगे आना होगा। सफाई सिर्फ बजट देने से नहीं आती। उन्होंने कहा जैसे सत्याग्रही देश को गुलामी से आजाद कराता है वैसे स्वच्छाग्रही देश को गदंगी से आजाद कराता है।

मंहगी हुई बिजली?

राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग एक बार फिर राजस्थान डिस्कॉम के पक्ष में झुका हुआ नजर आया है। विनियामक आयोग ने इस बार मिली उपभोक्ताओं की सर्वाधिक आपत्तियों और शिकायतों को दरकिनार करते हुए करीब 10 फीसदी दाम बढ़ाने के डिस्कॉम के प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा दी।

इस बार भी गरीब, बीपीएल, छोटे उपभोक्ताओं और किसानों समेत हर श्रेणी की बिजली को महंगा कर दिया है। आयोग की इस प्रक्रिया को बिजली मामलों के जानकार उपभोक्ता संगठनों ने गैरवाजिब माना है। उल्लेखनीय है, उपभोक्ता के हित में पूर्व में दिए गए आयोग के आदेशों की डिस्कॉम पालना तक नहीं कर रहा।

-गोपाल कृष्ण हरितवाल, जयपुर

वरिष्ठजनों के लिए जल्द नई नीति

वरिष्ठजनों के स्वास्थ्य की देखभाल और उनकी आवास सुविधा के लिए केन्द्र सरकार जल्द एक नई राष्ट्रीय नीति लाने की तैयारी में है। इस बारे में तैयार परिपत्र को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सामने प्रस्तुत किया जा चुका है।

बहरहाल, इस बारे में उन्होंने जल्द फैसला किए जाने की उम्मीद जताई है। यह प्रस्ताव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की देखरेख में विभिन्न विभागों के साथ विचार विमर्श के बाद तैयार किया गया है।

बनेंगे सवा लाख जल संग्रहण स्त्रोत

राजस्थान में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान का दूसरा चरण 16 नवम्बर से शुरू होगा। इसमें 4200 गांवों और शहरों में सवा लाख नए जल संग्रहण स्त्रोत या ढांचों का निर्माण कराया जाएगा। पहले चरण के सात माह में 3529 गांवों में 93 हजार 230 जल संग्रहण ढांचे बनाए गए हैं।

यह जानकारी चिकित्सा मंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने कृषि पंत भवन में हुई बैठक में देते हुए बताया कि दूसरे चरण के बाद शेष रहे गांवों में भी जल संग्रहण ढांचे विकसित किए जाएंगे।

दो हजार गांवों में बनेंगे गौरव पथ

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में गौरव पथ निर्माण के लिए दूसरे चरण में दो हजार ग्राम पंचायत मुख्यालयों का और चयन किया गया है।

इसके लिए 1200 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। पहले चरण में करीब दो हजार किलोमीटर लंबे गौरव पथ का निर्माण किया गया था। गुणवत्ता को लेकर मिल रही शिकायतों की थर्ड पार्टी से जांच कराने का भी प्रावधान किया गया है।

ग्राहक सुविधा केन्द्र

भारत सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्रालय के सौजन्य से 'कट्स' इन्टरनेशनल द्वारा ग्राहक सुविधा केन्द्र की स्थापना की गई है।

ग्राहक सुविधा केन्द्र

आप उपभोक्ता सम्बन्धित किसी भी तरह की जानकारी अथवा शिकायत के लिए निम्न पते पर सम्पर्क कर सकते हैं।

ग्राहक सुविधा केन्द्र
कंज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी (कट्स)
डी-218 ए, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016
ई-मेल: gsk@cuts.org फोन +091.141.4015395

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कट्स' जयपुर

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485